

FAST CHALLENGES TRAI'S TRADITIONAL ROLE

Television distribution is moving steadily from satellite, cable and DTH towards connected TV and internet-based services. That shift could alter the regulatory relevance of the carriage-focused framework traditionally associated with TRAI.

India's television ecosystem is entering a structural transition as Free Ad-Supported Streaming Television (FAST), connected TV (CTV) and application-based linear channels expand across internet-connected devices.

TRAI's broadcasting interventions have historically focused on distribution issues such as interconnection, tariffs, quality of service and broadcaster-distributor relationships. These regulations were designed around identifiable distribution platforms, including cable and DTH networks.

CTV introduces a different model. A channel accessed through an application on a smart TV over broadband does not necessarily involve a conventional distributor between the broadcaster and viewer. A subscription channel could similarly reach consumers directly through an application, potentially reducing the importance of traditional carriage arrangements.

TRAI has already acknowledged this emerging category. Its April 2026 consultation paper on Application-based Linear Television Distribution (ALTD) services covers applications distributing linear channels through smart TVs, mobile devices and web platforms, including FAST services.

India could consequently develop two parallel television ecosystems: the established satellite, cable and DTH environment, and a growing IP-based ecosystem comprising FAST services, broadcaster applications, CTV platforms and subscription-based linear channels.

As television distribution moves online, content regulation, consumer protection, advertising, age safeguards and platform accountability could become increasingly important alongside traditional carriage regulation.

The long-term question is therefore not simply whether FAST should be regulated, but whether a regulatory framework designed around television carriage can remain central when television is increasingly accessed through the internet. ■

ट्राई की पारंपरिक भूमिका को चुनौती दे रहा है फास्ट

टेलीविजन वितरण धीरे-धीरे सैटेलाइट, केबल और डीटीएच से हटकर कनेक्टेड टीवी और इंटरनेट आधारित सेवाओं की ओर बढ़ रहा है। यह बदलाव ट्राई से जुड़े पारंपरिक 'कैरिज केंद्रित' रेगुलेटरी ढांचे की अहमियत को बदल सकता है।

भारत का टेलीविजन तंत्र एक संरचनात्मक परिवर्तन की दौर से गुजर रहा है, क्योंकि 'फ्री-ऐड-सपोर्टेड स्ट्रीमिंग टेलीविजन (फास्ट)', कनेक्टेड टीवी (सीटीवी) और आवेदन आधारित लीनियर चैनल इंटरनेट से जुड़े उपकरणों पर व्यापक रूप से फैल रहे हैं।

ट्राई के प्रसारण से जुड़े दखल अब तक वितरण से जुड़ी समस्याओं पर केंद्रित रहे हैं, जैसे इंटरकनेक्शन, टैरिफ, क्वालिटी ऑफ सर्विस और प्रसारक-वितरक के बीच संबंध। ये नियम केबल और डीटीएच नेटवर्क जैसे पहचाने जा सकने वाले वितरण प्लेटफॉर्म को ध्यान में रखकर बनाये गये थे।

सीटीवी एक अलग मॉडल प्रस्तुत करता है। ब्रॉडबैंड के माध्यम से स्मार्ट टीवी पर किसी भी आवेदन के जरिए देखे जाने वाले चैनल के लिए प्रसारक और दर्शक के बीच पारंपरिक वितरक की आवश्यकता नहीं होती है। सब्सक्रिप्शन चैनल भी इसी प्रकार सीधे आवेदन के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंच सकते हैं, जिससे पारंपरिक वितरण व्यवस्था का महत्व कम हो सकता है।

ट्राई ने इस उभरती श्रेणी को पहले ही स्वीकार कर लिया है। अप्रैल 2026 में जारी एप्लीकेशन-आधारित लीनियर टेलीविजन वितरण (एएलटीडी) सेवाओं पर इसके परामर्श पत्र में स्मार्ट टीवी, मोबाइल उपकरण और वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से लीनियर चैनल वितरण करने वाले आवेदन भी शामिल हैं, जिसमें फास्ट भी शामिल है।

परिणामस्वरूप, भारत में दो समानांतर टेलीविजन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो सकते हैं: स्थापित सैटेलाइट, केबल और डीटीएच वातावरण और एक बढ़ता हुआ आईपी आधारित पारिस्थितिकी जिसमें फास्ट सेवाएं, प्रसारक अनुप्रयोग, सीटीवी प्लेटफॉर्म और सब्सक्रिप्शन आधारित लीनियर टेलीविजन चैनल शामिल हैं।

जैसे-जैसे टेलीविजन का वितरण ऑनलाइन हो रहा है, पारंपरिक कैरिज रेगुलेशन के साथ-साथ कंटेंट रेगुलेशन, उपभोक्ता संरक्षण, विज्ञापन, उम्र से जुड़ी सुरक्षा और प्लेटफॉर्म की जवाबदेही भी ज्यादा अहम हो सकती है।

इसलिए लंबे समय के नजरिए से सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या फास्ट को रेगुलेट किया जाना चाहिए, बल्कि यह है कि क्या टेलीविजन कैरिज के आधार पर बनाया गया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तब भी मुख्य बना रह सकता है, जब टेलीविजन को इंटरनेट के जरिए ज्यादा देखा जा रहा है। ■

